डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 अक्टूबर, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

| वर्ष 68 | अंक 10 | भोपाल | 16 अक्टूबर, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सभी सहकारी संस्थान अपने बैंक अकाउंट सहकारी बैंकों में खोले

- सहकारिता ही वह आर्थिक मॉडल है, जिसमें सभी के हित का ख्याल रखा जाता है
- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद जिला सहकारी (ADC) बैंक के 'स्वर्णिम शताब्दी महोत्सव' को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के कामकाज में आ रहे अवरोधों को दूर कर उन्हें आगे बढ़ा रहा है
- ADC बैंक का NPA शून्य होना उसकी पारदर्शिता का प्रमाण
- ADC बैंक ने 'छोटे लोगों का बड़ा बैंक' का मंत्र सही मायने में चरितार्थ किया
- अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक भारत में सबसे अधिक मुनाफा दर्ज करने वाला जिला सहकारी बैंक
- सभी सहकारी संस्थान अपने बैंक अकाउंट सहकारी बैंकों में खोले
- सहकारिता ही वह आर्थिक मॉडल है, जिसमें सभी के हित का ख्याल रखा जाता है
- कम पूँजी वाले कई लोगों को इकट्ठा करके बड़ी पूंजी का रूप देकर उन्हें काम करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उन्हें समृद्ध करना और उनके सम्मान पूर्ण जीवन की व्यवस्था करना ही सहकार है

अहमदाबाद। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद जिला सहकारी (ADC) बैंक के 'स्वर्णिम शताब्दी महोत्सव' को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई संस्था कई उतार–चढ़ाव देखते हुए ईमानदारी से काम करके 100 साल पूरे करे तो यह सिर्फ उस संस्था की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह तब और भी अहम हो जाता है जब वह कोई संस्था सहकारी हो, जिसका उद्देश्य अपने लिए काम करना नहीं बल्कि समाज के छोटे-छोटे लोगों को साथ जोड़कर सामूहिक प्रगति करने का हो।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 1925 में स्थापित अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का 100 साल पूरा होना अहमदाबाद जिले के किसानों के उत्कर्ष के सौ साल की कहानी है। उन्होंने कहा कि सौ साल पहले दस्करोई में एक छोटी संस्था बैंक के रूप में स्थापित हुई और आज 100 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ देश की सबसे मजबूत जिला सहकारी बैंक के तौर पर काम कर रही है। श्री शाह ने कहा कि लगभग शून्य NPA (Non-Performing Asset), 100 करोड़ रूपये का मुनाफा और साढे छह हजार करोड़ रूपये की जमा राशि वाले ADC बैंक के बारे में शायद ही किसी ने स्थापना के समय कल्पना की होगी कि यह छोटा सा बीज इतना बड़ा वटवृक्ष बन कर अनेक लोगों का कल्याण करेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि ADC बैंक ने सौ साल तक कई सोसायटियों, लाखों किसानों और कई पशुपालकों के जीवन में प्रकाश फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज कई तरह की कृषि सहायताएं सरलता से उपलब्ध हैं, परंतु जब इस बैंक की स्थापना हुई, तब किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। किसानों के पास साहूकारों के पास अपनी ज़मीन गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय यदि सूखा पड़ता था और किसान ऋणदाताओं के पैसे नहीं चुका पाते थे तो किसान, किसान नहीं रह कर खेतिहर मजदूर बन जाता था। श्री शाह ने कहा कि उस समय महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभभाई पटेल से कहा कि गुजरात में सहकारिता क्षेत्र की शुरुआत करनी चाहिए और फिर त्रिभुवनदास पटेल और सरदार पटेल जैसे सहकारिता क्षेत्र के कई अग्रणी व्यक्तित्वों ने गुजरात में सहकारिता का कार्य आरंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में सहकारिता के इस सौ–सवा सौ साल के इतिहास का काफी बड़ा योगदान है और यह योगदान आने वाले सौ साल में बढ़ने का पूरा यकीन है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दुनिया में अर्थव्यवस्था के कई तरह के मॉडल हैं। दो-तीन करोड़ की आबादी वाले छोटे देशों ने कई सफल मॉडल बनाए हैं। उन देशों में विकास का पैमाना सिर्फ आर्थिक विकास है, परंतु सवा सौ करोड़ की आबादी वाले भारत में ऐसे मॉडल सहायक नहीं हैं। श्री शाह ने कहा कि सिर्फ आर्थिक विकास से देश की प्रगति नहीं होती। जब तक 130 करोड़ की आबादी के काम, उनके सम्मान और उनके सुख का ख्याल नहीं हो, तब तक कोई भी आर्थिक मॉडल भारत जैसे देश में सफल नहीं हो सकता। यह आर्थिक मॉडल अगर कहीं मिलता है तो वह सहकारिता आंदोलन और सहकारिता के क्षेत्र में है।

श्री अमित शाह ने कहा कि 120 साल पहले जब भारत में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ, उस समय इस क्षेत्र की जितनी सापेक्षता थी, उससे ज्यादा सापेक्षता आज है। देश में इसके कई सफल उदाहरण हैं। उन्होंने गुजरात के अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि अमूल से जुड़कर 35 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि एक भी महिला ने 100 रूपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया है और आज अमूल का टर्नओवर 60 हजार करोड़ रूपये है। श्री शाह ने कहा कि पिछले दिनों गांधीनगर में बनासकांठा की एक महिला को जब डेयरी से जुड़े उसके काम के लिए 80 लाख रुपए का बैंक चेक मिला तो वह बहुत खुश हुई और यह उसके सशक्तिकरण को दर्शाता है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन होने के नाते जब वह गाँवों में जाते थे तो लोग कहते थे कि यह छोटे लोगों का बड़ा बैंक है। उन्होंने कहा कि ADC ने छोटे लोगों का बड़ा बैंक का मंत्र सही मायने में चरितार्थ किया है। श्री शाह ने कहा कि कम पूँजी वाले कई लोगों को इकट्ठा करके बड़ी पूंजी का रूप देकर उन्हें काम करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, उन्हें समृद्ध करना और उनके सम्मान पूर्ण जीवन की व्यवस्था करना ही सहकार है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले लगभग 70 साल से मांग की जा रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 साल से देश के इतने बड़े सहकारिता आंदोलन से जुड़े काम कृषि मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव संभाल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तीन साल पहले भारत सरकार में स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की रचना करके सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी आज़ादी के 75 साल मनाये, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का काम हुआ। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं कि 25-30 साल बाद जब उनका सही तरीके से विश्लेषण होगा तब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के निर्णय को काफी अहम फैसलों में गिना जाएगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि कभी काफी मुश्किलों से गुजर चुका अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक आज भारत में सबसे अधिक मुनाफा दर्ज कर रहा जिला सहकारी बैंक है। उन्होंने कहा कि इस बैंक के सफल होने में सेवा सहकारी सोसायटियों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि सेवा सहकारी सोसायटियों के कामकाज में कई तरह के प्रशासनिक अवरोध थे। लेकिन पिछले तीन साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह सारे अवरोध दूर किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सेवा सहकारी सोसायटियों के पास गोदाम हो, उनका कम्प्युटराइजेशन हो, उन्हें शून्य ब्याज पर ऋण मिले, सेवा सहकारी सोसायटी जल समिति चला सके, गैस सिलिंडर की एजेंसी ले सकें और पेट्रोल पंप का संचालन कर सकें। उन्होंने कहा कि यह राज्य का विषय है, फिर भी हमने इसके मॉडल बाय-लॉज़ बनाए। देश की सभी राज्य सरकारों ने इन बाय-लॉज़ को अपनाया। आज देश की सभी सेवा सहकारी मंडलियाँ एक ही तरह के नियमों और अकाउन्टिंग सिस्टम से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेवा सहकारी मंडली ग्रामीण स्तर पर वाइब्रेंट यूनिट बनेंगी। इनमें कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं। सेवा सहकार सोसायटी केन्द्र और राज्य सरकार की 300 तरह की योजनाओं का लाभ पाने का स्थान बनीं, जिससे सहकारिता आंदोलन अधिक मज़बूत हुआ है। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

सहकारिता के कार्यालयों को किया जाये रिडिजाइन : श्री सारंग

सर्वेयर और समिति प्रबंधक की हो हाई क्लास ट्रेनिंग ● मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता विभाग की बैठक में दिये निर्देश

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने निर्देश दिये है कि सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों को रिडिजाइन किया जाये। ऑफिस को अपडेट रखे, उसका डिजिटाइजेशन भी हो। मोटिवेशन स्लोगन लगाये जाये। सभी प्रकार के पेक्स के माध्यम से किसानों को भी शिक्षित करने का कार्य किया जाये। वहाँ उनके उपयोग की जानकारी हो। डिसप्ले के माध्यम से किसानों की हित की जानकारी का प्रदर्शन हो।

मंत्री श्री सारंग ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपार्जन के लिये सर्वेयर और समिति प्रबंधक की हाई क्लास ट्रेनिंग करवाई जाये। इसके लिये कम से कम 600 चयनितों का उपयोगी प्रशिक्षण हो। उपार्जन के समय पानी, बैठक व्यवस्था आदि का इंतजाम भी करें।

सहकारिता के प्रोडक्ट सेल करने नियत स्थान हो

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सारे विभागीय काम टाइम लिमिट में हो। सभी प्रक्रिया पारदर्शी हो। उन्होंने बैठक में स्वच्छता पखवाड़े में विभाग द्वारा किये गये कार्यों का प्रेजेन्टेशन भी देखा। साथ ही निर्देश दिये कि अच्छे काम करने वाले को अवार्ड/रिवार्ड दिया जाये। इससे अधिकारी-कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे। श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता के प्रोडक्ट सेल करने के लिये एक नियत स्थान का चयन भी किया जाये, जिसमें आसानी से एक ही स्थान पर सभी तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध रहें।

समितियों का निरीक्षण करें

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अधिकारी समय-समय पर समितियों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी समितियों का निरीक्षण करेंगे। सोसायटी के माध्यम से किसान जागरूक हो, इसके लिये सोसायटी के पास जानकारी उपलब्ध हो। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उपार्जन सिस्टम का रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर सिस्टम को रिडिजाइन करे।

बैठक में बारदाना और वित्तीय व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय निर्देशक द्वारा बताया गया कि प्रदेश में भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य अनुसार 29 जिलों में 23 बी-पेक्स के माध्यम से 23 नये एफ.पी.ओ. गठित हो चुके है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को सीबीबीओ बनाया गया है।

बैठक में विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री आलोक कुमार सिंह, पंजीयक श्री मनोज कुमार सरियाम, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा और सुश्री शीला दाहिमा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों ने अनेकों सार्थक मुद्दे उठाये, कृषि मंत्री होने के नाते मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि किसान कैसे आगे बढ़ें व कृषि क्षेत्र की हालत कैसे ठीक हो : श्री चौहान

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में किसान और किसान संगठनों से चर्चा की

किसानों से चर्चा के दौरान राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दे सामने आये, उन पर गहराई और गंभीरता से विचार करेंगे: श्री चौहान

किसान साथियों से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और इनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है: केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान और किसान संगठनों से संवाद के क्रम में नई दिल्ली में किसान संगठनों के सदस्यों से चर्चा की। श्री चौहान ने किसान महापंचायत के प्रमुख और उनके संघ के अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों व किसानों का स्वागत किया। किसान संगठनों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की व सुझाव दिये।

श्री चौहान ने बताया कि आज मेरा सौभाग्य है कि किसान महापंचायत के प्रमुख रामपाल सिंह और उनके संघ के अलग-अलग राज्यों के अनेकों किसान प्रतिनिधियों से बहुत सार्थक चर्चा हुई। हमने कई चीजों का गहराई से अध्ययन किया है। किसानों से चर्चा के दौरान राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दे सामने आये हैं, उन पर गहराई और गंभीरता से विचार करेंगे। कृषि मंत्री होने के नाते मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि किसान कैसे आगे बढ़ें व कृषि क्षेत्र की हालत कैसे ठीक हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं। किसानों के साथ संवाद उनकी समस्याओं को समझने में बहुत मदद करता है। श्री चौहान ने कहा है कि किसान महापंचायत के प्रमुख रामपाल सिंह ने कहा कि किसान के लिए काम हो। किसानों ने अनेकों सार्थक मुद्दे उठाये हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई चीजें हो रही हैं। किसानों के हित में पिछले दिनों लगातार अनेकों फैसले किये गये हैं जैसे कृषि विकास योजना में लचीलापन- इसमें प्रावधान किया है कि जिस राज्य के लिए जो योजना उपयुक्त हो वह वहीं काम करे। ऐसी कई चीजों पर काम हुए हैं और ऐसी कई चीजों पर काम होने की आवश्यकता है। किसानों ने फसल बीमा योजना सहित कई चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। हम पूरी गंभीरता से इन समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान साथियों से मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं और इनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फसल बीमा का क्लेम लेने में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ऋणी और अऋणी किसानों में सवैच्छिक हो। कई बार यह देखने में आया है कि स्वैछिक नहीं है तो उसे भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाता है आदि कई चीजों पर चर्चा हुई है।

‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु तीन पहलों के कार्यान्वयन जल्द जमीनी स्तर पर शुरू किया जाए

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने एवं मजबूत करने के बारे में सहकारिता मंत्रालय की दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक भुवनेश्वर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई

राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का मुख्य एजेंडा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रत्येक गांव/पंचायत में शुरू की गई प्रमुख पहलों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और इस कार्य को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर शुरू करना था

ओडिशा के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा ने कहा कि सहकारी समितियां एक ही छत के नीचे किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली ‘वन स्टॉप शॉप’ में बदल गई हैं

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि मंत्रालय ने देश भर में इन पहलों की सुचारू निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए वास्तविक समय में डेटा संग्रह और एक निर्बाध संरचना के निर्माण की योजना हेतु एनसीडी डेटाबेस के माध्यम से डिजिटलीकरण पर काम किया है

नई दिल्ली। देश में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक का उद्घाटन ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा ने किया और इसमां सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का एक प्रमुख एजेंडा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हाल ही प्रत्येक गांव/पंचायत में में शुरू की गई तीन प्रमुख पहलों से संबंधित एसओपी का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और इस कार्य को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर शुरू करना था।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा शुरू की गई तीन प्रमुख पहलों से संबंधित एसओपी में दो लाख नए एमपैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों का गठन व सुदृढ़ीकरण, ‘श्वेत क्रांति 2.0’ से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और ‘सहकारी संगठनों के बीच सहयोग’ शामिल हैं। इस दो दिवसीय समीक्षा बैठक में पैक्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्यात के अवसर प्रदान करके एक जीवंत आर्थिक इकाई बनाने के लक्ष्य पर भी चर्चा की गई।

सरकार के पहले 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई दस पहलों में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू की गई तीन प्रमुख पहलें शामिल हैं।

इस बैठक का उद्देश्य मंत्रालय की 100-दिवसीय कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना था। इस बात पर चर्चा की गई कि सहकारी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में सहकारी समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणालियों का आधुनिकीकरण काफी महत्वपूर्ण है।

ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा ने जमीनी स्तर पर ऐसे मजबूत संस्थानों के गठन और प्रचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें स्थानीय लोगों की गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण संरचना, प्रसंस्करण संबंधी सुविधाएं, ऋण संबंधी सुविधाएं और विपणन संबंधी सुविधाएं जैसी सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

अमूल जैसी बहु-राज्यीय सहकारी समितियों का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि मॉडल उपनियम, कम्प्यूटरीकरण, जन औषधि केन्द्रों जैसी सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं पहलों ने इन सहकारी समितियों को एक ही छत के नीचे किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने वाली ‘वन स्टॉप शॉप’ में बदल दिया है। जनता का अपना संगठन होने के नाते सहकारी समितियों में अपार संभावनाएं हैं।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस दिशा में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मॉडल उपनियमों को अपनाकर एमपैक्स के गठन पर जोर दिया। मॉडल उपनियमों को अपनाने से पैक्स को बहु-आयामी बनने में मदद मिली है और यह 25 नए व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करने में सक्षम हो गया है, जो आर्थिक रूप से पैक्स को मजबूत करेगा। इसके अलावा, तीन नई सहकारी समितियों एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल के गठन ने पैक्स के लिए क्षितिज को व्यापक बना दिया है। ये समितियां किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों सहित उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करेंगी।

उन्होंने बताया कि एक बड़े कदम के रूप में, सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी पहलों की सुचारू निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए वास्तविक समय में डेटा संग्रह और एक निर्बाध संरचना के निर्माण की योजना हेतु एनसीडी डेटाबेस के माध्यम से डिजिटलीकरण पर काम किया है।

डॉ. भूटानी ने कहा कि देश में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने हेतु, अगले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत सहकारी सदस्यों को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से नियमित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के सहकारी विभागों से नवंबर, 2024 में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन में भाग लेने का भी अनुरोध किया।

फोर्टिफाइड चावल का नि:शुल्क वितरण दिसम्बर-2028 तक जारी रहेगा

भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने केन्द्र सरकार के दिसंबर-2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि फोर्टिफाइड चावल वितरण का उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है।

प्रदेश में 5 करोड़ 45 लाख हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण

मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नि:शुल्क फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। आँगनवाड़ी केन्द्रों और मध्यान्ह भोजन के लिये भी फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिमाह लगभग 1.75 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इससे लगभग 5 करोड़ 45 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

क्या है फोर्टिफाइड चावल- भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अनुसार सामान्य चावल में पोषक तत्व मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-बी एवं जिंक सम्मिलित हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व लोगों की आहार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाते हैं।

सरस मेले में क़रीब 30 राज्यों की 900 से ज़्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी लेंगी भाग

ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा सरस आजीविका मेले का गुरूग्राम में 29 अक्टूबर 2024 तक आयोजन

मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण हेतू विशेषकर लर्निंग पैवेलियन एवं नॉलेज शेयरिंग पैवेलियन भी होंगे

नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरूग्राम के सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में लगातार तृतीय/तीसरे वर्ष सरस आजीविका मेला आयोजित किया जा रहा है। सरस मेले में क़रीब 30 राज्यों की 900 से ज़्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग ले रही हैं। मेले में विभिन्न राज्यों के उत्पाद जैसे तसर की साड़ियाँ, बाघ प्रिंट, गुजरात की पटोला साड़ियाँ, पश्चिम बंगाल की काथा की साड़ियाँ, राजस्थानी प्रिंट, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ। हिमाचल-उत्तराखंड के ऊनी उत्पाद व प्राकृतिक खाद्य उत्पाद, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के वूडन उत्पाद, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट व हैंडलूम के विभिन्न उत्पाद, झारखंड के पलाश उत्पाद व प्राकृतिक खाद्य सहित मेले में पूरे भारत की ग्रामीण संस्कृति के विविधता भरे उत्पाद प्रदर्शित होंगे।

इस बार मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण हेतू विशेषकर लर्निंग पैवेलियन एवं नॉलेज शेयरिंग पैवेलियन भी बनाये जायेंगे, जिनके माध्यम से समूह की दीदियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों (ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न विभाग, कृषि और किसान कल्यानण मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय इत्यादि) द्वारा उनकी योजनाओं के अन्तर्गत समूह की दीदियों को जोड़ने एवं जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों की जानकारी के विषय में अवगत कराया जायेगा एवं उनके कौशल विकास हेतू विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, गुरूग्राम सरस मेले में सरस फ़ूड कोर्ट भी लगाया जायेगा जिसमें क़रीब 25 राज्यों के 50 लाईव फ़ूड स्टाल लगाये जायेंगे। राजस्थानी कैर सांगरी-गट्टे की सब्ज़ी से लेकर बंगाल की फ़िश करी, तेलंगाना का चिकन, बिहार की लिट्टी चोखा, पंजाब का सरसों का साग व मक्के की रोटी सहित पूरे भारत के पकवान भी होंगे।

मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा बच्चों के खेलकूद व मनोरंजन के लिए किड्स जोन की व्यवस्था भी की गई है। मेले में दिल्ली-गुरूग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लाखों दर्शक व ग्राहक भाग लेंगे। दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पारदर्शिता को देखते हुए इस सरस आजीविका मेले में स्वयं सहायता समूहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन /नोमिनेशन की व्यवस्था की गई है। मेले में झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों से बी. सी. सखी एवं पत्रकार दीदियों की भी भागीदारी रहेगी।

इस बार गुरूग्राम सरस मेले में नॉर्थ-ईस्ट पैवेलियन भी स्थापित किया गया है ताकि उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्राथमिकता दी जा सके तथा हर राज्य को प्राथमिकता देने हेतू उनके लिए राज्यवार पैवेलियन बनाये जायेंगे। मेले में स्वास्थ्य सेवा हेतू मेडिकल हेल्प डेस्क एवं एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतू एवं मेले को सफल बनाने के लिए गुरूग्राम जिला प्रशासन एवं हरियाणा राज्य आजीविका मिशन का भी योगदान लिया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पिछले 26 वर्षों से सरस मेलों का आयोजन कर रहे हैं। इससे लाखों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साधन मुहैया हुए हैं व लाखों महिलाओं ने विपणन के हुनर सीखे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीन दयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सरस मेलों के माध्यम से मार्केटिंग का प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रहा है। सरस मेलों के माध्यम से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को शहरी ग्राहकों से सीधे संवाद करने व बाजार की रूचि जानने व उसी के अनुसार अपने उत्पादों की पैकेजिंग सुधार करके उत्पादों का मूल्यन निर्धारण करने का अवसर मिलता है।

सरस मेलों के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं न केवल आजीविका के अवसर सृजन कर रही हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण देश के सामने पेश कर रही हैं। यह निश्चित रूप से आजीविका यात्रा में एक मील का पत्थर है। सरस मेले वर्ष 1999 से निरंतर आयोजित हो रहे हैं। इन मेलों के माध्यम से लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने हेतु कृषोन्नति योजना (केवाई) को मंजूरी दी

अपेक्स बैंक का विशेष ऋण महोत्सव 8 अक्टूबर से शुरु

भोपाल : अपेक्स बैंक की सभी शाखाओं द्वारा "विशेष ऋण महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वितरित किये जाने वाले विभिन्न व्यक्तिगत ऋणों पर ब्याज की दरों में 0.50 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ ग्राहकों को दिया जायेगा। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दशहरा एवं दीपावली के शुभ-अवसर पर 8 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ग्राहक इसका लाभ ले सकते हैं।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता ने सभी शाखा प्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। इसमें आवास ऋण, पर्सलन लोन, वाहन लोन, अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण, लोडिंग ऑटो ऋण, रूफटॉप सोलर ऋण सहित अन्य ऋणों पर .50 प्रतिशत विशेष छूट का लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

81 लाख किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्त किया आभार

किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20 हजार करोड़ राशि अंतरित

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त राशि से प्रदेश के 81 लाख किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ की राशि मध्यप्रदेश के किसानों के खाते अंतरित की गई। डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

"संपदा-2.0", ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन में डिजिटल क्रांति का माइलस्टोन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नवीन तकनीक पर आधारित नवाचार ने बनाया सभी का जीवन सरल और सुगम

राज्य सरकार के नवाचार "संपदा-2.0" को पूरा देश करेगा फॉलो

"ईज ऑफ लिविंग" के लिये प्रदेश को नई सौगात

पंजीयन की व्यवस्था बनेगी सुगम, सरल और करप्शन-फ्री

केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को दिया 120 शहरों के जीआईएस मैपिंग का कार्य

हर जिले में स्थापित होगी जीआईएस लैब

ई-रजिस्ट्री और ई-पंजीयन की नवीन प्रणाली पर विकसित "संपदा-2.0" पोर्टल और मोबाइल ऐप का हुआ शुभारंभ

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन अब कल्पवृक्ष की तरह आमजन की हर जरूरत पूरी कर रहा है। जीरो बैलेंस खाता, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई- रजिस्ट्री जैसे नवाचार ने सभी का जीवन सरल और सुगम बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में नवीन तकनीक पर आधारित "संपदा-2.0" का नवाचार ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन में डिजिटल क्रांति का माइलस्टोन बनेगा। इस नवाचार को पूरा देश फॉलो करेगा। पहले प्रदेश में दस्तावेज पंजीयन और अन्य कार्यों के लिए कार्यालय आना पड़ता था लेकिन पोर्टल और ऐप के माध्यम से सभी लोग घर से ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ई-रजिस्ट्री और ई-पंजीयन के नवीन प्रणाली पर विकसित "संपदा-2.0" पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 2 नए महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं। इसमें 120 शहरों के जीआईएस कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आईटी विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित करने जा रहे हैं। इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश बहुत उन्नति कर रहा है। आईटी में नवाचार के साथ मध्यप्रदेश सरकार पेपरलेस सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "संपदा-2.0" की खूबियां बताते हुए कहा कि "संपदा-2.0" उन्नत तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें राजस्व वित्त विभाग और नगरीय प्रशासन के साथ जीएसटी और युनिक आईडी आधार से भी इंटीग्रेटेड किया गया है। जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर ऐप में लोकेशन के माध्यम से मालूम हो सकेगी। सॉफ्टवेयर से संपत्ति की जीआईसी मैपिंग होगी, बायोमैट्रिक पहचान और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग भी होगी। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण हो सकेगा। दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप और ईमेल से आवेदक को प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश लगातार नवाचार कर रहा है। इस दिशा में प्रदेश में संपदा-2.0 की नई व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशानुरूप ईज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जा रही है। इससे पंजीयन की व्यवस्था सुगम, सरल ओर करप्शन-फ्री बनेगी। नागरिकों को ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग की नवीन प्रणाली का लाभ मिलेगा। लोग घर बैठे अपनी प्रापर्टी को बेच भी सकेंगे और रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस प्रणाली से प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के बाहर से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ करवाई जा सकेंगी। इससे आम व्यक्ति का समय भी बचेगा और अनावश्यक रूप से लगने वाले आरोपों से मुक्ति भी मिलेगी।

ई-पंजीयन कराने वालों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई-पंजीयन एवं ई-स्टांपिंग के नवीन साफ्टवेयर "संपदा-2.0" का शुभारंभ कर इसका लाभ लेने वाले नागरिकों से वर्चुअल संवाद भी किया। हाँगकांग से श्री सुरेन्द्र सिंह चक्रावत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया कि "संपदा-2.0" के माध्यम से उन्होंने हाँगकांग से ही रतलाम में "पॉवर ऑफ अटार्नी" दस्तावेज का पंजीयन करवाया है। इसी प्रकार जबलपुर में जन्मी 78 वर्षीय बुजुर्ग डॉ. शक्ति मलिक जो वर्तमान में दिल्ली में निवासरत है, उन्होंने भी "संपदा-2.0" के माध्यम "पॉवर ऑफ अटार्नी" दस्तावेज का पंजीयन ऑनलाइन करवाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से संवाद में डॉ. मलिक ने बताया कि म.प्र. में की गई इस नई व्यवस्था से वे बेहद प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि जो काम मुझे रतलाम जाकर करना पड़ता, वह दिल्ली में बैठे-बैठे हो गया।

जो स्पेन में नहीं हुआ, वह हुआ मध्यप्रदेश में : श्री मरियानो मटियास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से वर्चुअल संवाद में स्पेन के श्री मरियानों मटियास ने बताया कि आज तक स्पेन में भी ई-रजिस्ट्री का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद के साथ कहा कि जो काम स्पेन में नहीं हुआ, वह मध्यप्रदेश ने उनके नेतृत्व में टीम ने करके दिखा दिया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वर्क कॉंट्रेक्ट का ऑनलाईन पंजीयन "संपदा-2.0" से कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों और दिल्ली में मौजूद स्पेन से आये श्री मरियोनो मटियास अलवरेज अर्स की कंपनी Ayesa Ingeniera Y Arquitecura S.A.U. एवं श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता (Ayesa India Pvt Ltd) द्वारा किया गया।

देश में रजिस्ट्री पंजीयन की डिजिटल प्रक्रिया में मध्यप्रदेश अग्रणी - उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश में रजिस्ट्री पंजीयन की डिजिटल प्रक्रिया में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशन में "संपदा-2.0" का सरलीकरण एवं सुधार द्रुत गति से हुआ है। प्रदेश की जनता के लिये दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीयन के पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों में सफलतापूर्वक संचालन के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया पूर्णत: पेपरलेस होने से गलतियों की गुंजाईश नहीं रहेगी। मोबाईल ऐप से किसी भी लोकेशन की गाईड लाइन दर तत्काल प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंजीयन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में "संपदा-2.0" पोर्टल और ऐप पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान श्रीकृष्ण का चित्र भेंट किया।

इस अवसर पर विधायक श्री भगवान दास सबनानी, विधायक श्री विष्णु खत्री, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव श्री अमित राठौर सहित संबंधित अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे। महानिरीक्षण पंजीयक एवं मुदांक श्री एम.सेल्वेंद्रन ने सभी का आभार माना।

किसान भाई अपनी आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग को अपनाने : उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाह

भोपाल : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि किसान भाइयों को उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। किसान भाई सरकार से अनुदान लेकर फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित कर सकते हैं। साथ ही अनुदान के आधार पर किसान छोटे, मध्यम और बड़े कोल्ड स्टोर भी स्थापित कर सकते हैं। इनमें किसान अपनी फसल सुरक्षित रखकर जब ऊँचे दाम हों, तब बेच सकते हैं। कृषि के साथ उद्यानिकी के माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा आसानी से बनाया जा सकता है। उन्होंने यह बात ग्वालियर जिला पंचायात सभागार में किसान सम्मान निधि राशि वितरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कही।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त सिंगल क्लिक के जरिए जारी की है। इसका विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रसारण किया गया। जिसमें ग्वालियर जिले के एक लाख 5 हजार 988 किसानों के खातों कुल 21 करोड़ 19 लाख 76 हजार रूपए की धनराशि पहुँची है। कार्यक्रम में सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों का पुष्पाहारों से मंत्री श्री कुशवाह ने आत्मीय स्वागत किया तथा प्रमाण-पत्र व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए। ग्वालियर जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना।

महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल बना मध्यप्रदेश

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन सरकार की पहली प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ.यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। महिला के सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर उन्हें आत्म-निर्भर बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण का "मध्यप्रदेश मॉडल" देश में अनूठा है, जिससे प्रेरित होकर अन्य राज्यों ने भी मध्यप्रदेश की महिला कल्याण की योजनाओं का अनुसरण कर अपने राज्यों में लागू किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बात चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर परिवार को पक्की छत देने की हो, या घर-घर शौचालय बनाकर खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की। नल-जल योजना से घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना हो या उज्ज्वला योजना से रसोई को धुंआ मुक्त बनाने का संकल्प हो। इन सभी योजनाओं का प्रदेश में बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन हुआ है। इसके अलावा महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिये महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें स्व-रोजगार से न केवल जोड़ा है, बल्कि उन्हें लखपति दीदी भी बनाया है। आज समूह की महिलाएँ के द्वारा निर्मित उत्पाद बाजारों में बिक रहे हैं। साथ ही उनका विक्रय ऑनलाइन मॉर्केटिंग से भी किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 81 प्रतिशत बढ़ा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के हर संकल्प को पूर्ण करने शिद्दत से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 81 प्रतिशत बढ़ाते हुए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें लाड़ली बहना योजना के लिये 18 हजार 984 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाड़ली बहनें इस योजना से लाभान्वित हो रही है। राज्य सरकार उनके मान-सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण फैसले

- राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके नाम जमीन, दुकान और घर की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त छूट दी है। इससे बहनों के पास संपत्ति की शक्ति आई है और समाज में उनका मान बढ़ा है।
- सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना अंतर्गत 19 लाख से अधिक बालिकाओं के बैंक खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया है।
- मध्यप्रदेश में महिलाओं को निकाय चुनाव एवं शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत, पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत और अन्य भर्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
- स्टार्ट-अप नीति में भी महिलाओं के लिये विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कुल स्टार्ट-अप्स में से 47 प्रतिशत की मालकिन महिलाएं हैं।
- महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई।
- मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्यु दंड देने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है।
- मध्यप्रदेश में महिलाओं से जोर-जबरदस्ती से या बहला-फुसला कर विवाह और धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया।
- बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये लाड़ली लक्ष्मी योजना का सफल क्रियान्वयन जारी है। योजना में 48 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मियाँ लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना से प्रदेश में लिंगानुपात में भी सुधार परिलक्षित हुआ है।
- प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना में अब तक 42 लाख महिला हितग्राही पंजीकृत हो चुकी हैं। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना और द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है।
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिये महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संचालित है।
- संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिये प्रत्येक जिले में वन-स्टॉप सेंटर संचालित हैं।
- बालिकाओं में आत्म-विश्वास और कौशल वृद्धि के लिये सशक्त वाहिनी कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। अब तक 128 बालिकाओं का पुलिस/ शासकीय विभागों में चयन हो चुका है।
- प्रदेश में 97 हजार से अधिक संचालित आंगनवाड़ियों में 81 लाख बच्चे और गर्भवती/धात्री माताएँ एवं किशोरी बालिकाएँ लाभान्वित हो रही हैं। आंगनवाड़ियों में ऑनलाइन उपस्थिति और आंगनवाड़ी एसेट्स डायरी सुविधा प्रारंभ की गई है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के साथ सहभागिता करने वाली महिला खिलाडियों को नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया गया।

पृष्ठ 1 का शेष)

सभी सहकारी संस्थान अपने बैंक अकाउंट ....

श्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात सहित पूरे देश में 'सहकारिता में सहकार' के प्रयोग को सफल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सहकारी संस्थानों के बैंक अकाउंट सहकारी बैंकों में होना चाहिए। बनासकांठा और पंचमहाल में यह मॉडल सफल हुआ है। अब पूरे गुजरात में इसे लागू करना है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 6 महीने में 6000 करोड़ रुपये की डिपॉजिट, 24 लाख बैंक अकाउंट खोलने और 80 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम सहकारी आंदोलन के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात के सहकारी बैंकों में सरप्लस है। पहले लोन लाने की चिंता थी, अब लोन देने की चिंता हो रही है, क्यूंकि डिपॉजिट बढ़ गई है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने गांधीनगर और अहमदाबाद के विकास के लिए काफी अच्छे काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में शताब्दी महोत्सव की पुस्तक का विमोचन और कॉफी टेबल बुक का अनावरण हुआ, कुछ दिव्यांग नागरिकों की सहायता के लिए उन्हें साधन मुहैया कराए गए, लेकिन यह नेक काम रुकने नहीं चाहिए। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, सभी कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMC) और सेवा सहकारी समितियों को ऐसे काम हमेशा जारी रखने चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की जिम्मेदारी है कि वह पूरे जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के विषयों को लेकर तमाम सहकारी संस्थाओं को एकजुट करे और एक कार्य योजना बनाकर हर गांव में उसे लागू करे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का कम्प्युटरीकरण हुआ और उसके बनाए कई तरह के अकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर को भारत सरकार ने NABARD के माध्यम से स्वीकार करके देश के सभी बैंक को देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का समान रूप से निर्वहन किया है। आज पांच प्रतिशत तक NPA भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंजूर किया है, लेकिन इस बैंक का NPA करीब शून्य है। NPA लगभग शून्य होना इस बात का प्रमाणपत्र है कि यह बैंक कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त और संस्कृत के प्रखर पंडित थे, जिन्होंने विदेश में भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की।

धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिये अभी तक 1.95 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल : धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये अभी तक 1.95 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 14 अक्टूबर, 2024 तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि समिति स्तरीय उपार्जन केन्द्र से ही अधिक से अधिक धान राइस मिलर्स को दी जायेगी। इससे समय पर मिलिंग का कार्य होने के साथ ही परिवहन और भण्डारण व्यय में भी बचत होगी। श्री राजपूत ने इस कार्य की सतत समीक्षा करने के निर्देश आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को दिये हैं।

आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन श्री सिबि चक्रवर्ती ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की समय-सीमा में तथा न्यूनतम व्यय पर मिलिंग कराने के लिये मध्यप्रदेश चावल उद्योग महासंघ के पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 2300 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 46 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन की तैयारी की जा रही है।

किसानों को शीघ्र भुगतान एवं परिवहन व्यय को सीमित करने के लिये गोदाम स्तरीय केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा धान मिलिंग की समय-सीमा जून-2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा में मिलिंग करने के लिये चावल महासंघ के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूँ के आवंटन में वृद्धि करने के कारण उपार्जित धान से निर्मित लगभग 60 प्रतिशत चावल भारतीय खाद्य निगम को परिदान करना होगा। इसके लिये मिलिंग प्रारंभ अवधि से ही भारतीय खाद्य निगम को चावल का परिदान मिलर्स को करना होगा। उपार्जित धान में से मिलिंग क्षमता अनुसार धान का प्रदाय मिलर्स को किया जायेगा, जिससे सभी मिलर्स को मिलिंग के लिये धान प्राप्त हो सके।

चावल महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा विगत वर्ष के लंबित भुगतान, उपार्जन केन्द्र से सीधे धान प्राप्त करने में सूखत मान्य करने तथा अपग्रेडेशन राशि के निर्धारण शीघ्र करने का अनुरोध किया गया। मिलिंग के लिये प्रदाय की जाने वाली धान के लिये उपार्जन एजेन्सी द्वारा ली जाने वाली अमानत राशि में बैंक गारंटी/एफडी राशि कम लेने सहित अन्य विषयों पर भी ध्यान दिलाया गया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बड़ी जोत वाले किसानों से अपनी सोसायटी से खाद लेने का आग्रह

ग्वालियर : बड़ी जोत वाले जिले के किसानों के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से रबी मौसम के लिए खाद (उर्वरक) वितरित किया जा रहा है। यहां से वे सुविधाजनक तरीके से खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों से रबी मौसम के लिए अपनी सहकारी समितियों से खाद (उर्वरक) प्राप्त करने की अपील की गई है।

उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर एस शाक्यवार ने बताया कि बड़ी जोत वाले किसान भाइयों को खाद लेने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विपरणा संघ के गोदामों या बाजार तक न जाने पड़े इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है।

युवा उद्यमियों, एफपीओ व अन्य संस्थाओं को सौंपी जाएगी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं

ग्वालियर : जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर स्थापित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन युवा उद्यमियों व संस्थाओं को सौंपा जाएगा। इन प्रयोगशालाओं में मृदा (मिट्टी) के नमूनों का परीक्षण किया जाता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन लेने के इच्छुक युवा उद्यमियों एवं संस्थाओं से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर एस शाक्यवार ने बताया कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आवंटित कराने के लिए पोर्टल http://www.mponline.gov.in पर स्वयं अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया ग्वालियर जिले की विकासखंड स्तरीय प्रयोगशाला घाटीगांव, डबरा तथा भितरवार में स्थापित हैं। कृषि स्नातक युवा उद्यमी, कृषि संबद्ध संस्थाएं एवं कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) व कृषक उत्पादक कंपनी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी के लिए मेला रोड स्थित उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में विभागीय वेबसाइट http://www.mpkrishi.mp.gov.in पर भी जानकारी उपलब्ध है

जिले में खाद की उपलब्धता

शिवपुरी :जिले में वर्तमान में 38777 मै. टन खाद उपलब्ध है। उर्वरक पर्याप्त मात्रा में निजी एवं सहकारी केंद्रों पर भण्डारित है। किसान भाई आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उठाव कर सकते है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने बताया कि जिले में वर्तमान में खाद की स्थिति में 13811 मै. टन यूरिया, 2073 मै.टन डीएपी, 5410 मै. टन एनपीके, 16917 मै. टन एसएसपी, 566 मै. टन एमओपी उपलब्ध है। जिले में 1 अक्टूबर से आज दिनांक तक 10424 मै. टन खाद वितरण हो चुका है। जिसमें 3029 मै. टन यूरिया, 3563 मै. टन डीएपी, 2971 मै. टन एनपीके, 719 मै. टन एसएसपी, एवं 142 मै. टन एमओपी है।

चंदेरी कस्बे का "प्राणपुर" ग्राम शिल्प कला में देश भर में बना "सिरमौर"

भोपाल : नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने देश के "टॉप-5" शिल्प कला ग्रामों में मध्यप्रदेश के अशोकनगर के चंदेरी कस्बे के "प्राणपुर" ग्राम को सर्वश्रेष्ठ शिल्प कला में चुने जाने पर बधाई और शुभकामना दी है। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मध्यप्रदेश के चंदेरी में बनने वाली साड़ी को "साड़ियों की रानी" कहा जाता है। अशोकनगर जिले के चंदेरी कस्बे के प्राणपुर ग्राम को देश के सर्वश्रेष्ठ पांच शिल्प कला के ग्रामों में "सिरमौर" होने का तमगा केंद्र सरकार ने दिया है।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री शुक्ला ने कहा है कि हमारा प्रदेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के लिए पूरे देश में पहचाना जाता है। इस धरा ने हमें ऐसी ही नयाब विरासत में चंदेरी की शिल्प कला दी है। चंदेरी के प्राणपुर ग्राम को देश के टॉप 5 शिल्प कला के ग्रामों में चुना गया है। इससे मन प्रफुल्लित हो उठा है। साथ ही इस कला को सहजने और संवारने एवं संरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने खिताब जीतने पर अशोकनगर जिले के शिल्पकारों को खास तौर पर चंदेरी के लोगों को बधाई दी है।

लघु वनोपज संग्रहण से जुड़े एसएचजी को वन-धन केन्द्रों से जोड़ा जायेगा : वन मंत्री

लघु वनोपज संग्रहणकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम

भोपाल : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने कहा कि लघु वनोपज संग्रहण से जुड़े एसएचजी को वन-धन केन्द्रों से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि श्योपुर जिले में वनोपज की बहुलता है और यहाँ के हजारों परिवार वनोपज संग्रहण से जुड़े हुए हैं। श्री रावत ने कहा कि क्षेत्र में तेन्दूपत्ता से लेकर विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। वन मंत्री श्री रावत जनपद पंचायत कराहल के सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र में लघु वनोपज संग्रहणकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वन-धन केन्द्रों के माध्यम से वनोपज संग्रहणकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

वन मंत्री श्री रावत ने संवाद के दौरान महिलाओं की माँग पर कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर की स्थापना तथा उनसे संघों को जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वन-धन केन्द्र से इन समूहों को जोड़ने की प्रक्रिया की जायेगी। साथ ही वनोपज संग्रहण से जुड़े परिवारों को मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

इस अवसर पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन गोरस की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता, बरगवा सीएलएफ की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति, आवदा सीएलएफ की उपाध्यक्ष श्रीमती गुड्डी ने भी संवाद कार्यक्रम में अपने विचार रखे। एनआरएलएमडीपीएम श्री सोहन कृष्ण मुद्गल ने बताया कि कराहल क्षेत्र में 3647 समूह संचालित हैं, जिनमें 40 हजार के लगभग महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। कराहल क्षेत्र में सहरिया लघु वनोपज प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का संचालन भी किया जा रहा है। इस कम्पनी से एनआरएलएम के समूह जुड़े हुए हैं, जो वनोपज संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। संवाद कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी और जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन की व्यवस्थाओं संबंधी बैठक आयोजित

अशोक नगर : कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन हेतु जिले में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने निर्देश दिए कि जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण की जाएं। उन्होंने उपार्जन समितियों को निर्देशित किया कि किसानों का पंजीयन अधिक से अधिक कराया जाए। उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की व्य वस्था,धर्मकाटा,परिवहन,मापदण्ड तथा सुरक्षित भण्डारण हेतु समूचित व्यवस्थाएं की जाएं। खरीदी केंद्रों पर आने वाले कृषकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सोयाबीन की व्यवस्थित रूप से तोल हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिले में खाद की उपलब्धता,भण्डारण एवं वितरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आगामी रैक के आने पर सहकारी समितियों को उर्वरक

पहुंचाए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में उप संचालक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री के.एस.केन द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जिले में सोयाबीन उपार्जन की प्रक्रिया के तहत 20 अक्टूबर तक किसानों के पंजीयन किए जा रहें हैं। बैठक में बताया गया कि सोयाबीन उपार्जन के लिये किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन चल रहा है। किसान सोयाबीन विक्रय के लिये आगामी 20 अक्टूबर, 2024 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकृत किसानों से सोयाबीन की खरीदी (उपार्जन) 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की जायेगी। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विटंल 4892 रूपये की दर से उपार्जन किया जायेगा। बैठक में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री एस.के. जैन,डीएमओं मार्कफेड श्री रितिक ताम्भ्रे,सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग श्री अभिषेक कुमार जैन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थें।

कृषि विभाग और मार्कफेड जिले में उर्वरक की उपलब्धता देखें,दुकानों पर इसकी उपलब्धता के साइन बोर्ड्स लगवाना सुनिश्चित करें - कलेक्टर

धार : सभी राजस्व अधिकारी अपने अनुभाग अंतर्गत समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी के लिए 20 अक्टूबर तक चलने वाले पंजीयन की व्यवस्थाएं के साथ ही इस तारीख़ तक ख़रीदी की सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी करवा लें। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा 25 अक्टूबर से खरीदी आरंभ करने की तिथि निर्धारित की गई है।कृषि विभाग और मार्कफेड जिले में उर्वरक की उपलब्धता देखें,दुकानों पर इसकी उपलब्धता के साइन बोर्ड्स लगवाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत सहित समस्त राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने अधिकारियों से कहा की शासन की नीति अनुसार जिले में गोदामों पर बनाए जाने वाले खरीदी केंद्रों पर विशेष फोकस रखें। सभी राजस्व अधिकारी वन ग्राम से राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन के कार्यों में प्रगति लाकर शेष ग्रामों को शीघ्र पूरा करें। संबंधित अधिकारी लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल पर समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों का निराकरण

सुनिश्चित करे। साथ ही तीन दिवसों में समय सीमा में बाह्य होने प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करें। सभी तहसीलदार राजस्व वसूली पर जोर देवें।साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाली संभागायुक्त की बैठक का एजेंडा अनुसार तैयारी रखे। राजस्व अभियान अंतर्गत की गई कार्यवाहियों के पालन प्रतिवेदन नही भेजने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करें। साथ ही इनकी एक एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके। इसके अलावा बटवारे के पोर्टल पर अपलोड करने के बचे प्रकरणों को आगामी दो दिवस में अपलोड करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए की पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत मृत हितग्राहियों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही शीघ्र करें। साथ ही इसके अंतर्गत दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो नही करने पर सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करें। उन्होंने पीएम किसान के अंतर्गत ई केवाईसी के शेष प्रकरणों को अगले 4 दिनों में मिशन मोड में लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारी फ़ौति एफआरए नामांतरण में भी प्रगति लाएं। इसके अलावा वन अधिकारी पट्टों के हितग्रहियों को पीएम किसान का लाभ दिलाने की शेष कार्यवाही को भी शीघ्र करें। सभी अधिकारी स्वामित्व योजना अंतर्गत शेष कार्यवाहियों को पूरा करें। इसके लिए अपने पटवारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। इसके अंतर्गत आरओआर एंट्री की कार्यवाही लगातार जारी रख कर शीघ्र पूर्ण करें। मजरा टोला के शेष कार्यों में सभी तहसीलदार कार्यवाही जल्दी करे। इसके अलावा शेष डायवर्जन डाटा एंट्री में प्रगति लाएं। उन्होंने साइबर तहसील का रिव्यू करने उपरांत तहसीलदार धार और दिग्ठान को शेष बचे कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने लैंड बैंक के तैयारी, प्रति पूर्ति वनीकरण की स्थिति, भू-अर्जन के लंबित प्रकरण, भू-अर्जन के आदेश का रेकार्ड में अमल की स्थिति, मंदिरो से संबधित जानकारी एवं मंदिरों संबंधित कोर्ट केस की जानकारी, लोक परिसंपत्ति पोर्टल पर जिलों द्वारा दर्ज परिसंपत्तियां, भूमि आवंटन प्रकरण, सीएम मॉनिट सीएम हाउस, पीड़ित प्रतिकार से लंबित प्रकरण, आडिट कंडिका के संबंध में, राजस्व विभाग के निर्माणाधीन निर्माण कार्यों की प्रगति एवं लंबित कार्य, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अवमानना लंबित मामले महत्वपूर्ण समय से जवाब, न्यालयीन प्रकरणों में पी.एस.एवं सी.एस के नाम हटाने के संबंध में कार्यवाही, विभागीय परि संपतियों के अनुरक्षण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, बैंक आर.आर.सी. वसूली के संबंध में, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, अतिवृष्टि से हुई विभिन्न क्षति के सर्वेक्षण के संबंध में सहित अन्य विषयों की समीक्षा भी की।

71वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024
(14 से 20 नवम्बर 2024)
Main theme: Role of Cooperatives in building "Viksit Bharat"
मुख्य विषय: "विकसित भारत" के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका

14-11-2024	सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों से सहकारिता आंदोलन का सुदृढ़ीकरण।	Strengthening Cooperation Movement through New Initiatives of Ministry of Cooperation.
15-11-2024	सहकारिता में नवाचार, टेक्नोलोजी एवं सुशासन।	Innovation, Technology and Good Governance in Cooperative.
16-11-2024	उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास में सहकारिताओं की भूमिका।	The Role of Cooperatives in Fostering Entrepreneurship, Employment, and Skill Development..
17-11-2024	सहकारी उद्यमों का रूपांतरण।	Transforming Cooperative Enterprises.
18-11-2024	सहकारिताओं के बीच सहकार की भावना का सुदढ़ीकरण।	Strengthening Cooperation Among Cooperatives
19-11-2024	महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए सहकारिता।	Cooperatives for Women, Youth, and Weaker Sections,
20-11-2024	सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता की भूमिका एवं एक बेहतर विश्व का निमार्ण।	Role of Cooperatives in Achieving SDGs and way forward for Better World

बटिक स्टाल का निरीक्षण करते पंजीयक

भोपाल। नवाचार अंतर्गत गठित दीन दयाल महिला रंगाई छपाई सिलाई कढ़ाई बहुउद्देशीय अंत्योदय सहकारी संस्था उज्जैन द्वारा दिनांक 7.10.2024 को कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाये म.प्र. विंध्याचल भवन भोपाल में दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2024 तक संस्था में निर्मित बटिक प्रिंट वस्त्रों का स्टाल लगाया गया। स्टाल का पंजीयक श्री मनोज कुमार सरियाम द्वारा मौका मुआयना किया गया एवं इस कार्य की सराहना की गई एवं टीम को बधाई दी गई। इस अवसर पर श्री बी.एस. शुक्ला, अपर आयुक्त, श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल, श्री विमल श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त, श्री एच.एस. वाघेला, संयुक्त आयुक्त, श्री उमेश तिवारी, उपायुक्त, श्री आर.एस. विश्वकर्मा, उपायुक्त, श्री अरूण मिश्रा, उपायुक्त, श्री तुमूल सिन्हा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक भी उपस्थित रहे।

किसानों से डीएपी के स्थान पर एनपीके मिश्रित उर्वरकों का उपयोग करे

खरगोन : रबी सीजन में गेहूं, चना, मसूर की फसल लगाने के लिए किसानों द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों से अपील की गई है कि रबी फसलों के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके मिश्रित उर्वरकों का उपयोग करें।

उप संचालक कृषि श्री एमएस सोलंकी ने बताया कि जिले में एनपीके मिश्रित उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान अपनी सहकारी समिति केन्द्र से यह उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। किसान मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्रों से भी नगद भुगतान कर एनपीके उर्वरक क्रय कर सकते हैं। उप संचालक श्री सोलंकी ने बताया कि डीएपी के स्थान पर यूरिया एवं सुपर फास्फेट खाद का भी उपयोग किया जा सकता है। एनपीके मिश्रित उर्वरक डीएपी की तरह की अच्छा परिणाम देते हैं और फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अतः किसान डीएपी के स्थान पर एनपीके मिश्रित उर्वरक ही अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।